



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026। कैसर के इलाज पर होने वाले खर्च को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कैसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं के ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30 प्रतिशत तक सीमित करने की व्यवस्था की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होनी हैं। इस कदम का उद्देश्य कैसर मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। इस व्यवस्था के तहत संबंधित दवाओं के निमाताओं को निर्धारित सीमा से अधिक कीमत पर बिक्री होने की स्थिति में संशोधित एमआरपी लागू करनी होगी। हालांकि, दवाओं के वास्तविक कीमत में कितनी कमी आएगी, यह प्रत्येक दवा की मौजूदा कीमत, वितरक को उसकी आपूर्ति दवा में और निर्धारित गणना पद्धति पर निर्भर करेगा। 137 दवाओं पर लागू होगी नई व्यवस्था केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार सूची में कैसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं। इनमें एंटेजोलिडमुमैब, बेवासिमुमैब, डाराटमुमैब, एन्जाजोल्टामाइट, एलॉर्निटिब, इपिलिमुमैब और लैपॉर्टिबन जैसे दवाएं शामिल हैं। हालांकि, इन्फ्यूजेबल की चर्चित दवा कीटूडा को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए नई व्यवस्था से सभी कैसर दवाओं की कीमतों में समान रूप से कमी आने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

सकता। एनपीपीए के निर्देश के अनुसार, ट्रेड मार्जिन को गणना जीएसटी को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर की जाएगी। यह सीमा दवा की शक्ति, उसके स्वरूप और सेवन के तरीके को परवाह किए बिना लागू होगी। सूची में शामिल दवाओं के संयोगित वाले फॉर्मूलेशन भी निर्धारित शर्तों के अधीन इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। कैसे तब होगी दवाओं की नई कीमत? दवाओं की संशोधित एमआरपी की गणना के लिए मार्च 2026 में स्टीफिकर्ट याविरकर को दी गई कीमत को आधार बनाया जाएगा। यदि संबंधित दवा की उस महीने बिजली नहीं हुई थी, तो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के बिजली आंकड़ों के आधार पर कीमत निर्धारित की जाएगी। इस गणना में सरकारी बिजली को शामिल नहीं किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक एमआरपी पर दवा बेचने वाले निमाताओं को कीमत घटानी होगी। वहीं, जिन दवाओं की मौजूदगी एमआरपी पहले से निर्धारित सीमा से कम है, उनको कीमत बढ़ाने के बजाय मौजूद स्तर पर बचाए रखने का निर्देश है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि निमाताओं औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के तहत अनुमत वार्षिक मूल्य वृद्धि का लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेड मार्जिन संबंधी निर्धारित सीमा को पालन करना होगा। अस्पतालों को सीधे आपूर्ति पर भी नजर रख व्यवस्था 31 मार्च 2026 के बाद बाजार में उतारे गए उन फॉर्मूलेशन पर भी लागू

होगी, जिनमें सूचीबद्ध दवाओं में से कोई दवा शामिल है। यदि निमातां सीधे अस्पतालों या चिकित्सा संस्थानों को दवाओं की आपूर्ति करते हैं, तो निमातां मूल्य गणना के लिए इन संस्थानों को स्टॉकडेटा या वितरक के रूप में माना जाएगा। इसके लिए निमातां के बिल संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। दवाओं की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए निमातांओं को मौजूदा उत्पादन स्तर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। औसत अनुक्रमित घटने से पहले एम्पीपीए की अनुमति लेनी होगी। वहीं, उत्पादन या आयात बंद करने की स्थिति में कम से कम छह महीने पहले निमातांरित जानकारी देना आवश्यक होगा। मरीज सहायता योजनाओं पर भी निमातांरित दवा कंपनियों की मरीज सहायता योजनाओं के तहत मुफ्त वितरित की जाने वाली दवाओं के लिए कुछ छूट का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, इसका लाभ लेने के लिए कंपनियों को निमातांरित घोषणा-पत्र देना होगा और मरीजों चिकित्सकीय रिपोर्टें देना आपूर्ति तथा खपत का विस्तृत पत्रिकाई रखना होगा। एम्पीपीए को इन अभिलेखों की जांच, ऑडिट और निरीक्षण करने का अधिकार होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित छूट वापस ली जा सकती है। आदेश के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के सात दिनों के भीतर निमातांओं को संशोधित एम्पीपीए और निमातांरित एम्पीपीए और संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक को देनी

गोपी। यह जानकारी तब भी देनी होगी, जब किसी दवा की एमआरपी में बदलाव नहीं किया गया हो। इसके अलावा, निर्धारित प्रणाली के माध्यम से मूल्य सूची जारी करना भी आवश्यक होगा। नियम तोड़ने पर हर सकती कार्रवाई निर्धारित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में इसे कीमत कम करने के माध्यम से नकारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में डीपीसीओ के नियमों के तहत अधिक वसूली गई राशि को वसूली के लिए कार्रवाई की जा सकती है। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों से भी कहा गया है कि वे कैसरोधी दवाओं की एमआरपी पर नजर रखें और किसी भी अवसर पर उल्लंघन की सूचना प्राधिकरण को दें। राज्य सरकारों को निम्नलिखित नियंत्रकों की जिम्मेदारी होगी कि निर्णयों, वितरण, निष्पादन और संबंधित चिकित्सा संस्थान नियमों का पालन सुनिश्चित करें। कैसर का उपचार लंबे समय तक चलने के कारण मरीजों और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव डाल सकता है। निम्नलिखित बातें दवाओं के मूल्य और वितरण मार्गों पर निर्व्यय नियंत्रण राहत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। हालाँकि, इसका वास्तविक प्रभाव तभी सुनिश्चित होगा, जब संशोधित कीमतीत प्रभावी दंग से लागू हों, दवाओं की वितरण में वितरण उपलब्धता बनी रहे और बाजार में वितरण का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून लागू हो सके।



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026 | दिल्ली आयोगिक विकास को गति देने, निवेश कार्पाकित करने और रोजगार के नए अवसर को कनेक्ट करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण दम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नेतृत्व वाले मुहूर्त निवेश मंडल में आयोगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई। इस नीति में महिला उद्यमों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अतिरिक्त वित्तीय सहायता तथा निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। नीति के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी तथा एकल खिड़की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त निवेश से संबंधित विभिन्न अनुमतियों और प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना तथा उद्योग स्थापित करने में लागत को कम रखना प्रशासनिक बाधाओं को कम कर रहा है।

हेला उद्यमियों को आर्थिक मजबूती देने पर नई आयोगिक नीति में महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर

प्रत्यक्ष करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। नीति में महिलाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों की भी अधिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। इससे महिला रोजगार को बढ़ावा देने के साथ औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में मदद मिलने की सम्भावना है। हालांकि, वित्तीय सहायता की आवश्यकता राशि, पात्रता की शर्त और प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में अंतिम निर्णय अगले महत्वपूर्ण हंगामे 10 प्रथमकला वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा औद्योगिक नीति 2026 में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं (आईटी), डेटा सेंटर, स्वास्थ्य सेवाओं और लॉजिस्टिक्स सहित 10, प्रत्यक्ष सेवा वाले क्षेत्रों में निवेश को अधिकतम करने पर जोर दिया गया है। इस क्षेत्रों में पात्र निवेश के लिए 25 प्रतिशत तक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान बताया गया है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में आधुनिक उद्योगों के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने है। डेटा सेंटर और आईटी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से डिजिटल सेवाओं तथा तकनीकी रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। इसी तरह स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश से संबंधित सेवाओं की क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, 25 प्रतिशत तक प्रोत्साहन का लाभ केवल परियोजनाओं को मिलेगा और इसकी अधिकतम सीमा क्या होगी, यह निर्धारित नियमों तथा पात्रता मानदंडों पर निर्भर करेगा। इन्वेस्ट दिल्ली से निवेश प्रक्रिया होगी सरल नीति का एक प्रमुख उद्देश्य निवेशकों को विभिन्न वित्तीय कर्षकों प्रदान करने के लिए एकिकृत रूप उपलब्ध

है। इन्वेस्ट दिल्ली एकल खिड़की के माध्यम से आवेदन, अनुमतियों और संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा गया है। भाषापर और उद्योग जनत के लिए किसी भी शहर निवेश का निर्णय लेते समय अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया, समग्रबद्ध सेवाएं और नीतिगत प्रष्टता महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में एकल खिड़की के माध्यम से प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेश विभागों के जो लोग समन्वय कितनी प्रभावी रहता है और आवेदन कितनी प्रभावबद्धता से निपटाए जाते हैं। रोजगार और औद्योगिक विकास पर रहेगी नजर दिल्ली की औद्योगिक नीति का उद्देश्य और महिला उद्यमिता के साथ रोजगार सृजन और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इसके परिणामों का आकलन निवेश की वास्तविक मात्रा, नए उद्योगों की स्थापना, एम्प्लॉयमेंट को मिलने वाली सहायता और पैदा होने वाले रोजगार अवसरों के आधार पर किया जा सकेगा। निती की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी क घोषित प्रोत्साहन पात्र उद्यमियों और परिणतियों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं। मंजूर है, आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय प्रथु और योजनाओं को नियमित निगरानी महत्वपूर्ण होगी। दिल्ली सरकार की औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी निवेश और र्थमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम स्तर है। अगर इसके क्रियान्वयन से जुड़े प्रोत्साहन इस पहल के वास्तविक प्रभाव को र्धारित करेगी।

रूसी तेल की खरीद बढ़ाने की तैयारी में भारत, रोजाना 18 लाख बैरल आयात की चर्चा



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
 नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026। रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत की संभावित आयात रणनीति एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रूसी तेल पर अमेरिकी शुल्क संबंधी राहत मिलने के बाद भारत प्रतिदिन करीब 18 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद सकता है। यह मात्रा लगभग 28.62 करोड़ लिटर के बराबर बताई गई है। रिपोर्ट में इस संभावित आयात की तुलना

दिल्ली की ईंधन खपत से करते हुए कहा गया है कि इतनी मात्रा का तेल दिल्ली की मौजूदा खपत के हिसाब से करीब 40 दिनों की जरूरत के बराबर हो सकता है। हालांकि, यह एक तुलनात्मक अनुमान है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि आयातित कच्चे तेल से सीधे इतनी अवधि तक दिल्ली के सभी वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। अमेरिकी शुल्क में राहत से बढ़ सकती है दिल्ली रूसी तेल की खरीद पर अमेरिकी नीतियों का भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़ता रहा है। शुल्क संबंधी राहत से भारतीय तेल कंपनियों को रूस से खरीद के विकल्पों पर विचार करने में अधिक गुंजाइश मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक आयात की मात्रा अंतराष्ट्रीय

बाजार का स्थिति, कीमतों, भुगतान व्यवस्था और कंपनियों के व्यावसायिक निर्णयों पर निर्भर करेगी। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में विभिन्न देशों से तेल की आपूर्ति बनाए रखना ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 18 लाख बैरल यानी करीब 28.62 करोड़ लीटर प्रतिदिन रिपोर्ट में बताई गई संभावित मात्रा के अनुसार, भारत का रूसी तेल आयात प्रतिदिन 18 लाख बैरल तक पहुँच सकता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल माना जाता है। इस हिसाब से 18 लाख बैरल करीब 28.62 करोड़ लीटर कच्चे तेल के बराबर होते हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि कच्चे तेल को रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत करने के बाद पेट्रोल, डीजल और

नये पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसलिए कच्चे तेल की कुल मात्रा और उससे मिलने वाले उपयोगी ईंधन की मात्रा एक समान नहीं होती। दिल्ली की 40 दिन की ख़ास ख़पत से व्षों की गई तुलना? रिपोर्ट में इस संभावित आयत की तुलना दिल्ली की ईंधन ख़पत से की गई है। इसके अनुसार, बताई गई मात्रा दिल्ली की मौजूदा ख़पत के आधार पर लगभग 40 दिनों की जरूरत के बराबर हो सकती है। इस तुलना का उद्देश्य अयाव्यता को कम करना है। इस तुलना को आसानी से समझाना है। हालांकि, दिल्ली की वास्तविक ईंधन ख़पत, पेट्रोलियम उत्पादों की श्रेणियों और कच्चे तेल तैयार होने वाले उत्पादों के अनुपात के आधार पर यह तुलना अत्यंत ग़लत है। इसलिए इसे अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा और कीमती पर रहेगी नज़र भारत के लिए

सी तेल की खरीद का महत्व केवल आयात की मात्रा तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमते, रिवरहैन लागत, रुपये और डॉलर का अनुपात दर तथा आपूर्ति की स्थिरता भी पेरुलु की कीमतों को प्रभावित करती हैं। रूसी तेल को संभावित बढ़ी हुई खरीद से भारत को आपूर्ति के विकल्प बनाने रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी स्थिर रहने से कम होंगी, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। मिथिला, 18 लाख प्रतिदिन की मात्रा को मीडिया रिपोर्टों में व्यक्त प्रभावित आयात के रूप में देखा जाना चाहिए। स्वस्थिक खरीद की पुष्टि और अमेरिकी तेल संबंधी राहत की अंतिम शर्तें स्पष्ट होने बाद ही इसकी आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जा सकेगा।



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
 नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026। छह माह तक के शिशुओं के लिए तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पादों में अतिरिक्त शर्करा के इस्तेमाल पर रोक लगाने की दिशा में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने कदम बढ़ाया है। प्राधिकरण ने ऐसे उत्पादों में फ्रुक्टोज और सुक्रोज मिलाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक

निम्न, 2020 में संशोधन का मसौदा जारी कर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 60 दिनों के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी गईं। शिशु आहार में पोषण गुणवत्ता पर जोर देकर सार्वजनिक संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छह माह तक के शिशुओं के लिए बनाए जाने वाले खाद्य उत्पादों में आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हों और उनमें प्रतिरक्ति शर्करा न मिलाई जाए। शुरुआती 6 महीने के शिशुओं के पोषण को लेकर खाद्य उत्पादों में गुणवत्ता और संरचना महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रूक्टोज और सुक्रोज शर्करा के प्रकार हैं। फ्रूक्टोज लालू होने पर निर्धारित श्रेणी के शिशु खाद्य उत्पादों में इनके इस्तेमाल को लेकर निम्न चर्चाएं हो सकती हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव है; इसे अंतिम निष्कर्ष न बना उचित नहीं होगा।

दिल्ली में प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने का दावा, हर्ष मल्होत्रा ने आप-कांग्रेस को घेरा

भारतार्थ खबर
Bhaaraataarth.com

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026। केन्द्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों के प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन से दिल्ली की व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं और कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मल्होत्रा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी आपत्ति जताई। प्रदर्शन के स्थान को लेकर उठाए सवाल हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यदि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, तो राजनीतिक दलों को किसी अन्य निर्धारित स्थल पर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। उनके अनुसार, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किए जाने के बावजूद वहां प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। केन्द्रीय मंत्री ने दावा किया कि कर्नाट प्लेस सहित दिल्ली के कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में कारोबार क़रीब दस दिनों से प्रभावित है। उन्होंने

ए.एस.आई.आर और चुनाव आयोग पर विपक्ष से सवाल मतदाता सूची के विशेष गहन पुरीकरण पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में मल्होत्रा ने दावा किया कि देश में एस.आई.आर की प्रक्रिया पहले भी चलायी जा चुकी है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि



कि यदि यह प्रक्रिया पहले अपनाई गई थी, तो उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किया गया। उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष से चुनाव आयुक्त की भूमिका पर उठाए जा रहे सवालों का आधार सृष्टि करने की मांग की। मल्होत्रा ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से ऐसे लोगों को नमाल हटाए जाने चाहिए, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं। उनके अनुसार, मतदान

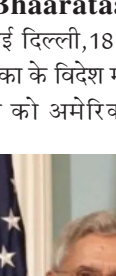
के तहत सारिता विहार वार्ड और ओखला विधानसभा क्षेत्र में कचरे के निस्तारण के लिए कॉम्पेक्टर मशीनों लगाई गई हैं। मल्होत्रा के अनुसार, ये मशीनें कचरे को खाकर उसका आकार लगभग दसवें हिस्से तक कम कर सकती हैं। इसके बाद कचरे को ट्रकों के माध्यम से निर्धारित स्थानों में पहुँचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कचरा एक हजार मशीनों लगाई गई हैं, जिनमें से 100 मशीनों को संबोधित वार्ड में हरी झंडी दिखाई गई। क्षेत्र में नए पिपर वाहत भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की व्यवस्था होगी। दिल्ली सरकार और नगर निगम के कामकाज पर भी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर कचरा प्रबंधन तथा बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सेबा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा करते हुए दया दिखाया कि नगर निगम को पर्याप्त नद उपलब्ध कक्षा जा रहा है और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है।

लंदन, 18 अक्टूबर 2026। ब्रिटेन की मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश प्रदर्शन का दूसरा पक्ष भी सामने आया। जू यूट्यूबर ध्रुव राठी के विरोध में भी लोग जुलूस को अलग-अलग रखा, ताकि आमने-सामने न भारतीय चुनाव व्यवस्था और प्रधानमंत्री रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच मतभेदों। प्रेमी समूह ने मोदी के समर्थन में किया प्रदर्श यूके के संस्थापक हद्देश गुप्ता ने भारत प्रेमी

राताार्थ.com

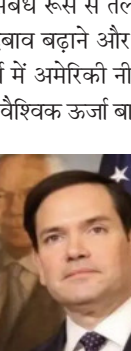
जघनजी लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में
र के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान विरोध-
बन्ध जानकार के अनुसार, शनिवार को
स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों समूहों
की स्थिति से बचा जा सके। इस घटनाक्रम
मोदी के नेतृत्व को लेकर विदेश में रह
सामाजिक रूप से सामने ला दिया। भारत
जावाबी प्रदर्शन के दौरान इंडिया डायस्पेरा
गों से एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के साथ मजबूती से खड़े रहने की
आपली को। उनके बहाने के
जरिए प्रदर्शन में शामिल मोदी
समर्थक समूह ने अपना पक्ष रखा।
एक ओर मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन
हो रहा था, वहीं दूसरी ओर
विरोधी पक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के
समर्थन में अपनी आवाज उठाई।
इस तरह पार्लियामेंट स्क्वायर में
की देखने को मिली। पुलिस ने दोनों गुटों

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026।
मेरिका के विदेश मंत्री मार्को रबियो ने
भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण



हयोगी बताते हुए संकेत दिया है कि

को 60 दिनों के लिए रोक रखा है। इस मुद्दे का संबंध रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने और रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिकी नीति से है। रूसी तेल और वैश्विक ऊर्जा बाजार बना अहम मुद्दा



रुबियो के अनुसार, भारत की ऊर्जा

स्तावित प्रतिबंधों और टैरिफ के अमेरिकी वर्धव्यवस्था तथा वैश्विक बाजार पर नबने वाले संभावित प्रभावों का आकलन करने हैं। हालांकि, इस अस्थायी रहत में भविष्य में टैरिफ नहीं लगाए जाने की थायी गारंटी नहीं माना जा सकता। भारत रे पर व्यापार और ऊर्जा संबंधेग पर होगी र्चा रबिगे अन्दरुबर में भारत दैरे पर आ र्ते हैं। इस यात्रा के दौरान व्यापार, ऊर्जा र्दहयेग और दोनों देशों के रणनीतिक र्दहयेग से जुडे मुद्दे पर र्चर्चा होने की उम्मीद । यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब र्दरत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर तर्दीनी जारी है और रूसी तेल की खरीद र्दर अमेरिकी ररख दोनों देशों के आर्थिक र्दरबंदों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। र्दर देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा, कफायती र्दर ल को उ पलाधनक्षता और र्दर प्रमुख र्दरव्यवस्था के त त प्रमुख र्दरथमकताए हैं। वहीं, अमेरिका रूस

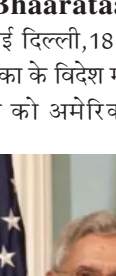
लंदन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच ध्रुव राठी का विरोध, मोदी समर्थकों ने भी बुलंद की आवाज

भारतार्थ खबर Bhaaratarth.com

लंदन, 18 अक्टूबर 2026। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीसीई) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान विरोध-प्रदर्शन का दूसरा पक्ष भी सामने आया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शनिवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के विरोध में भी लोग जुटे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों समूहों को अलग-अलग रखा, ताकि आमने-सामने की स्थिति से बचा जा सके। इस घटनाक्रम ने भारतीय चुनाव व्यवस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच मतभेदों को सार्वजनिक रूप से सामने ला दिया। भारत प्रेमी समूह ने मोदी के समर्थन में किया प्रदर्शन जबकी प्रदर्शन के दौरान इंडिया डायस्पेरा यूके के संस्थापक हर्देश गुप्ता ने भारत प्रेमी लोगों से एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहने की अपील की। उनके बयान के जरिए प्रदर्शन में शामिल मोदी समर्थक समूह ने अपना पक्ष रखा। एक ओर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर विरोधी पक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। इस तरह पार्लियामेंट स्क्वायर में अलग-अलग विचारों वाले समूहों की मौजूदगी देखने को मिली। पुलिस ने दोनों गुटों

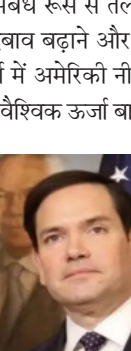
भारत अमेरिका का अहम सहयोगी, टैरिफ लगाने से पहले
वॉशिंगटन को करना होगा व्यापक विचार : रुबियो

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026।
मेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने
भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण



हयोगी बताते हुए संकेत दिया है कि

को 60 दिनों के लिए रोक रखा है। इस मुद्दे का संबंध रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने और रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिकी नीति से है। रूसी तेल और वैश्विक ऊर्जा बाजार बना अहम मुद्दा



रुबियो के अनुसार, भारत की ऊर्जा

स्तावित प्रतिबंधों और टैरिफ के अमेरिकी वर्धव्यवस्था तथा वैश्विक बाजार पर नोने वाले संभावित प्रभावों का आकलन करने हैं। हालांकि, इस अस्थायी रहत में भविष्य में टैरिफ नहीं लगाए जाने की थायी गारंटी नहीं माना जा सकता। भारत रे पर व्यापार और ऊर्जा संबंधों पर होगी र्चा रूबियों अन्दरुबर में भारत दैरे पर आ हैं हैं। इस यात्रा के दौरान व्यापार, ऊर्जा र्धयोग और दोनों देशों के रणनीतिक र्धयोग से जुड़े मुद्दों पर र्चा होने की उम्मीद । यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब रत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर तर्की जारी है और रूसी तेल की खरीद र अमेरिकी रूख दोनों देशों के आर्थिक र्धों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। रत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, फिकायित ल को उ पलाशधरता और र्ध प्रमुख र्धव्यवस्था के तित प्रमुख र्थमकताए हैं। वहीं, अमेरिका रूस

कहा कि दिवाली और शादी का सीजन नजदीक होने के बावजूद बाहर से आने वाले ग्राहक और व्यापारी दिल्ली आने से बच रहे हैं। हालांकि, कोरोनाबार में गिरावट और उसके कारणों से जुड़े इन दावों के समर्थन में स्वतंत्र लगाईके उपलब्ध नहीं कराए गए। महत्वा न आरोप लगाया कि आप और कांग्रेस आगामी चुनावों में संभावित हार की आशंका के चलते एएआईआर तथा चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक रूप दे रही हैं। ये आरोप केंद्रीय मंत्री ने विश्व के खिलाफ लगाए हैं; संबंधित हलों की प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं हैं।

का अधिकार और देश के संसाधनों से जुड़े अधिकारों के मामले में नागरिकता संबंधी निर्णयों का पालन जरूरी है। सेवा संकल्प अभियान के तहत कचरा प्रबंधन पर जो राजनीतिक भाष्य-प्रत्याशों के बीच महोत्सव ने दिल्ली में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान और कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू किए गए इस अभियान

मलहोत्रा ने ये पृष्ठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर नगर निगमों को पर्याप्त सख्तियों नहीं देने का आरोप भी लगाया। उनके अनुसार, मौजूदा सरकार के प्रवासों से दिल्ली में अनधिक सुविधाओं को बेहतर बनाने का कम्प आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन, व्यापारिक गतिविधियों और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच कारोबार पर सार्वजनिक प्रभाव का आकलन स्वतंत्र आंकड़ों और संबंधित व्यापारिक संगठनों की प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट हो सकेगा।

का रखा अलग प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था समूहों को एक-दूसरे से अलग रखा। इससे अलग-अलग सामंजसिक स्थान पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जानकारी में प्रदर्शनकारियों की संख्या, विरोधों की गई किसी अन्य कार्रवाई का ब्योरा नहीं। मुद्रों पर बस लंदन में हुआ वह घटनाक्रम राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े मुद्दे विदेशों में रहनेवाले का विषय बन रहे हैं। अलग-अलग विचारधारावादी समूहों में प्रदर्शन किया। ऐसे मामलों में प्रदर्शनकारियों सामझना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से होना तथा कानून-व्यवस्था

किसी संभावित टकराव को रोकने और का प्रयास किया गया। हालाँकि, उपलब्ध क्रिस्तुन कार्यों और पुलिस की ओर से गया है। विदेश में भी भारतीय राजनीतिक ताता है कि भारत की चुनावी व्यवस्था और ले भारतीय मूल के लोगों के बीच भी चर्चा वाले समूहों ने अपने-अपने रुख के समर्थन न वित्तियों और आरोपों को तथ्यों से अलग रखे हैं। विदेश में भी भारतीय राजनीतिक ताता है कि भारत की चुनावी व्यवस्था और ले भारतीय मूल के लोगों के बीच भी चर्चा वाले समूहों ने अपने-अपने रुख के समर्थन न वित्तियों और आरोपों को तथ्यों से अलग रखे हैं।

एखना महत्वपूर्ण है।

भारत पर अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाने से पहले ऊर्जा जरूरतों और उसके प्राणिक वैश्विक प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रस्तावित कड़े शुल्क के बीच संबंधों के इस रुख को भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त लगाने से संबंधित विधायी पहल

स्थिति को नजर अंदाज करते कोई केसला लेना उचित नहीं होगा। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और रूस उसके प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। ऐसे में रूसी तेल की खरीद पर अचानक प्रतिबंध बना या अतिरिक्त शुल्क लगाने से अक्सर बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन की 60 दिनों की समीक्षा अवधि का उद्देश्य

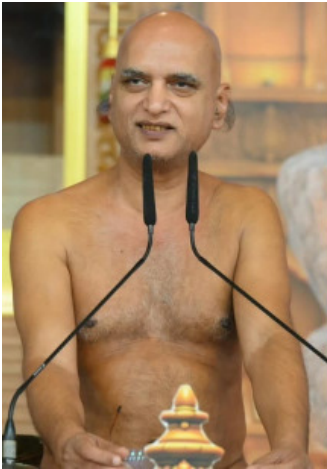
रा आर्थिक दबाव बनाए रखने की अपनी नीति के साथ सहयोगी देशों के संबंधों को भी संतुलित करना चाहता है। रूबियों के बयान से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन भारत की अर्थ-राजनीतिक अहमियत और ऊर्जा संबंधी रुचियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहता है। हालांकि, प्रस्तावित संयुक्त विज्ञापन पर अंतिम रुख और उसके परिणामों पर निर्भर करेंगे।

पीड़ा पर विजय और सामायिक की सही विधि का मुनि वीरसागर जी ने दिया मार्गदर्शन

भारतार्थ खबर
Bhaarataraarth.com

बेंगलुरु, 18 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु में आयोजित प्रतियोगिता शिविर के दूसरे दिन नित्योपक ब्रम्हण मुनि श्री 108 वीरसागर जी महाराज के सान्निध्य में साधकों को पीड़ा के चिंतन पर विजय पाने, समता भाव विकसित करने और सामायिक की व्यावहारिक प्रविचन के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया।

प्रथम सत्रों में आत्मचिंतन, मानसिक संतुलन, एकाग्रता और आत्मसंयम के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया। शिविर में बेंगलुरु सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए साधक-साधिकाओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। मुनि श्री मार्गदर्शन में धार्मिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन में अपनाने और साधना के मूल भाव को समझने पर जोर दिया गया। पीड़ा के बार-बार चिंतन से बचने का संदेश पीड़ा चिंतन जीतने का उपाय विषय पर मार्गदर्शन देते हुए मुनि श्री ने प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और समता बनाए रखने के महत्व को समझाया। जीवन में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में घटना से उत्पन्न कष्ट के साथ-साथ उत्पन्न बारे में बार-बार विचार करना भी मन की अशांति बढ़ा सकता है। प्रवचन का प्रमुख संदेश रहा कि परिस्थितियां



समता भाव को साधना का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। सुख-दुख, अनुकूलता-प्रतिकूलता और विभिन्न परिस्थितियों के बीच मन के परिणामों को संतुलित रखने का अभ्यास आत्मसंयम को मजबूत करने में सहायक होता है। मुनि श्री के मार्गदर्शन ने साधकों को पीड़ा के कारणों

को समझने के साथ अनावश्यक मानसिक व्याकुलता से बचने और आत्मबल विकसित करने की प्रेरणा दी। सामायिक केकेवल धार्मिक क्रिया नहीं, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शिविर के दूसरे दिन का एक प्रमुख विषय सामायिक करने का। व्यावहारिक विधि रहा। इस विषय पर मुनि श्री ने सामायिक के उद्देश्य और उसके आध्यात्मिक महत्व को समझाते हुए सभा, आत्मनिरीक्षण तथा एकमात्र के भाव पर जोर दिया। सामायिक जैन धर्म की महत्वपूर्ण साधना है, जिसमें साधक निर्धारित समय तक सासारिक गतिविधियों से विरत होकर आत्मचिंतन और संयम का अभ्यास करता है। इसकी साधना केवल निरार्थ अवधि पूर्ण करने में नहीं, बल्कि विधिपूर्वक साधना करने और उसके मूल भाव को समझने में निहित है। सामायिक के दौरान मन को स्थिर रखने, विचारों के प्रति सजग रहने और ध्यान को साधना में केन्द्रित करने का प्रयास आवश्यक है। मन का षट्काना साधक के सामने चुनौती बन सकता है, लेकिन निराशा होने के बजाय बार-बार अपने ध्यान को साधना की ओर लौटाने का अभ्यास किया जा सकता है। मुनि श्री के मार्गदर्शन में विधि, भाव और प्राकृतिक के महत्व को रेखांकित किया गया। साधकों को प्रेरित किया गया कि वे धार्मिक क्रियाओं को केवल परंपरा

या औपचारिकता के रूप में न अपनाएँ, बल्कि उनके उद्देश्य को समझकर अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। धर्म को दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर प्रवचन में धार्मिक सिद्धांतों और व्यावहारिक जीवन के बीच संबंध को भी रेखांकित किया गया। परिवार, कार्यस्थल और सामाजिक जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं, जिनमें व्यक्ति को धैर्य, विवेक और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानना तथा संतुलित व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करना आध्यात्मिक साधना का व्यावहारिक पक्ष बन सकता है। नियमित आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपनी कमियों को समझने और उनमें सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। प्रतिमाधारी शिविर के माध्यम से साधकों को इस बात पर विचार करने की प्रेरणा मिली कि धार्मिक नियमों और साधना को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव जीवन के व्यवहार में भी दिखाई दे सके। शंका-समाधान से साधकों को मिली स्पष्टता कार्यक्रम के दौरान साधकों ने साधना, अग्रगत और सामायिक के अन्धसा से संबंधित अपनी जिज्ञासाएँ भी

प्रस्तुत की मुनि श्री ने सरल उदाहरणों के माध्यम से विषयों को समझाने और साधकों की शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। इस संवादात्मक सत्र से प्रतिभागियों को अपनी जिज्ञासाओं पर विचार करने तथा धार्मिक साधना के व्यावहारिक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला। शिविर में साधक-साधिकाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही और वातावरण आध्यात्मिक श्रद्धा से परिपूर्ण दिखाई दिया। समता और आत्मचिंतन साधना के प्रमुख आधार प्रतिमाध्याय शिविर के दूसरे दिवस का मूल संदेश रहा कि प्रतिभूत परिस्थितियों में समता बनाए रखने का आश्वास और सामाजिक के माध्यम से आत्मनिरीक्षण, साधक के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीसगरजी महाराज के मार्गदर्शन से प्रतिभागियों को अपने विचारों एवं भावनाओं के प्रति जागरूक रहने, आत्मसंयम विवसित करने और नियमित साधना के महत्व को समझने की प्रेरणा दी। शिविर में प्रस्तुत विषयों ने धर्म को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित न रखकर उसे जीवन के व्यवहार में अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। समाचार प्रेषक विपिन कुमार जैन बेंगलूर



से जुड़ी सामग्री भी वितरित की गई। इसमें स्कुल बैग, लैपिंग्स, पानी की बोतल, जैकेट, बालों की सजावट से संबंधित सामग्री, कार्पिथान, रबर, पेंसिल और स्कुल के जूते शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक कन्या को दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक विदा किया गया। सेवा और सहयोग में समाज की सच्ची भागीदारी कार्यक्रम में। वृजकिशोर भूरा, हेमसु ड्रवर, कुणाल कोठारी, श्वेता बियाणी और निर्मला कांकाणी सहित संस्था की पूरी टीम तथा समाज की महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी सदस्यों ने आपसी सहयोग से आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया।

दुर्गा पूजा पर सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन की स्वास्थ्य पहल, 250 लोगों की निःशुल्क जांच



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
बेंगलुरु, 18 अक्टूबर 2026। दुर्गा
पूजा के अवसर पर समाज के जरूरतमंद
लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के
उद्देश्य से सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन और मां
दुर्गा सेवा समिति की ओर से
कामाक्षीपाल्या स्थित धनंजय पैलेस में
निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर



और दांतों की निःशुल्क जांच की गई। आयोजन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उन्हें नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के प्रति जागरूक करना था। फाउंडेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नीरज शर्मा के अनुसार, शिविर में प्रवासी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं, रसोइयों,

चालकों और अन्य मेहनतकश लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि कामकाज और आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई जरूरतमंद लोग समय पर स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाते। ऐसे शिविर उनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। 50 से अधिक लोगों में पहली बार स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने का दावा सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन के संस्थापक प्रवीण पांडेय ने

बताया कि शिविर के दौरान 50 से अधिक लोगों में पहली बार उच्च रक्तचाप और बढ़े हुए रक्त शर्करा स्तर का पता चला। उन्होंने कहा कि समय रहते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पहचान होने से प्रभावित लोगों को चिकित्सकीय परामर्श लेने और संभावित जटिलताओं से बचाव के लिए कदम उठाने में मदद मिल सकती है। पांडेय के अनुसार, सेवा बिग्रेड फाउंडेशन पिछले पांच वर्षों में 16 हजार से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर चुका है। संस्था जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक स्वास्थ्यसेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। आयोजकों ने सहयोगी संस्थाओं के प्रति जताया आभार मां दुर्गा सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील ठाकुर और सचिव मणिकांत झा ने शिविर के आयोजन में सहयोग के लिए सेवा बिग्रेड फाउंडेशन के सीईओ राम मोहन पाठक और संयुक्त सचिव प्रभात मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त

किया। उन्होंने स्पर्श हॉस्पिटल, यशवन्तपुर, ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रोक्वेयर डेंटल की टीमों के योगदान की भी सराहना की। शिविर के संचालन में सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन की ओर से प्रवीण पांडेय, प्रभाश, कमलेश यादव, राम मोहन पाठक, तौकीर, नीरज शर्मा और सुधीर सहित अन्य सदस्यों ने योगदान दिया। वहीं, मां दुर्गा सेवा समिति की ओर से मणिकांत झा, सुनील ठाकुर, अनिल शर्मा, प्रमोद सिंह, मुकेश और राजू ने सक्रिय भूमिका निभाई। आयोजकों ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के अवसर पर सेवा गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई, ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच का लाभ मिल सके। समाचार प्रेषक प्रवीण पांडेय बेंगलुरु।

हैदराबाद में कारोबारी का अपहरण कर 1.30 करोड़ रुपये वसूले, मास्टरमाइंड समेत 10 गिरफ्तार



भारतार्थ खबर
Bhaarataraarth.com
है दाराबाद, 18 अक्टूबर 2026।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक
ज्वेलरी कारोबारी के अपहरण और
फिरौती वसूली के मामले में पुलिस ने बड़ी
कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता
समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया
है। मामले में दो अन्य आरोपी फरार बताए
जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों
ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी बन कर
कारोबारी के . श्रीनिवासर्मा बच का
अपहरण किया और उन्हें छोड़ने के बदले
भारी रकम की मांग की। मॉडिया रिपोर्टों
के मुताबिक, अपहरण की घटना 5
अक्टूबर को हुई थी। आरोपियों को
कथित तौर पर कारोबारी से 15 करोड़
रुपये की फिरौती मांगी और बाद में 1.30
करोड़ रुपये वसूलने के बाद उन्हें रिहा

अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी से 1.30 करोड़ रुपये वसूल थे। पुलिस ने इनमें से लगभग 1.07 करोड़ रुपये बरामद कर लिए हैं। शेष राशि के संबंध में जांच और बरामदगी की स्थिति का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। पुलिस के सामने अब कथित साजिश में शामिल सभी लोगों की भूमिका, फिरोती की रकम के लेन-देन और फरार अपराधियों का पता लगाने जैसी चुनौतियाँ हैं। इन पहलुओं पर जांच आगे बढ़ने के साथ अधिक जानकारी सामने आने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था और फर्जी पहचान का गंभीर मामला इस घटना में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों बनाकर अपहरण किए जाने का पहलू विशेष रूप से गंभीर है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों की पहचान का दुरुपयोग आम लोगों में भ्रम पैदा कर सकता है और अपराधियों को वारदात अंजाम देने का अवसर दे सकता है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए संविध परिस्थितियों में संबंधित पुलिसकर्मियों की पहचान की पुष्टि करना और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारिक पुलिस हेल्पलाइन से संपर्क करना उपयोगी हो सकता है। हैदराबाद में कारोबारी के अपहरण का यह मामला फिरोती के लिए संगठित अपराध और पहचान के दुरुपयोग से जुड़ी चुनौतियों को सामने लाता है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जांच की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

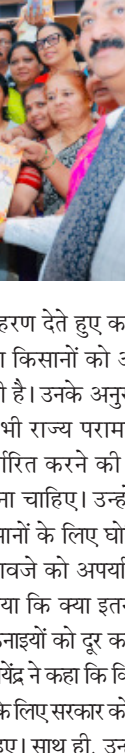
हुबली, 18 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने भाजी और जनता दल (सेक्युलर) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों को जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने विवासाव जताया कि 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में मराठाओं का समर्थन एनडीए उम्मीदवारों को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं, राज्य कृषिसे में कथित अरुन्नी खींतावन और कर्नाटक में लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। शंकरनूर को हैदिक का मौका, चारों सीटों पर जीत को तैयारी विजयेंद्र ने मौजूदा विधान परिषद सदस्य शंकरनूर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाई है। उनके अनुसार, शंकरनूर के पास लगतातार तीसरी जीत दर्ज करने का अवसर है और पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा-जद(एस) गठबंधन के उम्मीदवारों में शंकरनूर, के.एम. सुरेश, नमोशाल और बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ए.पी. रंगाथा शामिल हैं। विजयेंद्र ने कहा कि सभी चार सीटों पर जीत हासिल करने के लिए

गठबंधन के कार्यकर्ता मिलकर प्रयास कर रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए स्थायी समाधान की मांग गन्ना किसानों की समस्याओं पर विजयेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के



नेतृत्व वाला केंद्र सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है। उन्होंने गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) व्यवस्था और इथेनॉल नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों से चीनी उद्योग और किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि किसानों को गन्ने के भुगतान में देरी सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार, इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए समिति गठित किए जाने की जानकारी सामाने आई है। विजयेंद्र ने

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता मूल्य देने पर विचार करने की मांग की। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का



उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ राज्यों में गन्ना किसानों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है। उनके अनुसार, कर्नाटक सरकार को भी राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) निर्धारित करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सूखे से प्रभावित किसानों के लिए घोषित 2,500 रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए सवाल उठाया कि क्या इतनी राशि किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। विजयेंद्र ने कहा कि किसानों को प्रभावी राहत देने के लिए सरकार को अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही, उन्होंने किसानों से अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन

आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत आरोपों और हमलों से बचना भी जरूरी है। काग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर लागू आरोप विजयेंद्र ने काग्रेस नेता रहलु गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी हार के बाद काग्रेस संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग और अन्य संगठनों को लेकर सवाल उठाकर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि काग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय यह सामर्थ्यमंथन करना चाहिए कि जनता का भरोसा पार्टी से क्यों कम हो रहा है। राज्य काग्रेस में कथित अंदरूनी खींटाने पर विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व को लेकर असंतोष होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद और हालिया स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े घटनाक्रम आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो सकते हैं। विजयेंद्र ने यह भी दावा किया कि सदन पर विजयेंद्र चुनाव के बाद काग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। हालांकि, काग्रेस के भीतर कथित साजिशों और स्टिंग ऑपरेशन के पीछे के लोगों को लेकर लगाने गए उनके आरोपों की स्वतंत्र पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। इन दावों पर संबन्धित कृष्ण नेताओं का स्पष्ट भी सामने आना बाकी है। कैपीएससी भर्ती में पारदर्शिता और खाली पद भरे की मांग कर्नाटक लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए विजयेंद्र ने राज्य सरकार से अनिवार्यताओं की निष्पक्ष जांच कराए और भर्ती में हो रही देरी दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग को बंद

नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन और कन्या भोजन की परंपरा का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी परंपरा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में भोजन और शिक्षा के साथ शिक्षा से संबंधित सामग्री वितरित करना भी आयोजन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा। इससे धार्मिक आयोजन को सेवा और सामाजिक सहयोग से जोड़ने का प्रयास सामने आया। धार्मिक आस्था के साथ शिक्षा को प्रोत्साहन नारायणी की रसोई संस्था की इस पहल में कन्याओं का आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का विशेष ध्यान दिया गया। स्कूल बैग, कपड़ियाँ, पेंसिल और जूते जैसे वस्तुओं का वितरण शिक्षा से जुड़े जरूरतों के प्रति सहयोग की भावना को दर्शाता है। ऐसे आयोजन धार्मिक परंपराओं के साथ सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने का माध्यम बन सकते हैं। समाज के विभिन्न सदस्यों की भागीदारी से सेवा कार्यों का सामूहिक रूप दिया जा सकता है और कार्यक्रम ने आस्था, संवेदनशीलता और जरूरतमंदों की सहायता के महत्व को रेखांकित किया। नारायणी की रसोई संस्था द्वारा आयोजित यह कन्या भोजन कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर सेवा, सम्मान और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने वाली पहल के रूप में सामने आया।

गोवा में प्रदर्शन के दौरान कथित हिंदुत्व विरोधी नारे, 300 अज्ञात लोगों पर एफआईआर

भारतार्थ खबर Bhaaratarth.com

पणजी, 18 अक्टूबर 2026। गोवा की राजधानी पणजी में 11 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंदुत्व मुचाबंद के नारे लगाए जाने के मामले में पुलिस ने करीब 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 और 299 के तहत मामला दर्ज किया है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था। प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कथित नारों को लेकर मामला दर्ज होने के बावजूद यह घटनाक्रम चर्चा में आया है। पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य मामले से जुड़े आरोपों की जांच करना और संबंधित व्यक्तियों की पहचान करना है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान सात लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। हालाँकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। प्राथमिकी में करीब 300 अज्ञात लोगों का उल्लेख होने के कारण मामले में संबंधित प्रदर्शनकारियों में

पहचान और उनकी भूमिका की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस प्रकरण में आरोपों और जांच के निष्कर्षों के बीच अंतर करना आवश्यक है। प्राथमिकी दर्ज होना अपने आप में किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं है। मामले में संबंधित नारे किस संदर्भ में लगाए गए, उनको प्रकृति क्या थी और कानून के तहत किन व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है इसका निर्धारण जांच तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा। फिनाल उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से जांच के विस्तृत निष्कर्ष, सभी आरोपित व्यक्तियों की पहचान अथवा मामले की आगे की कार्रवाई का पूरा विवरण सामने नहीं आया है। इसलिए प्रकरण से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के आधिकारिक विवरण के आधार पर ही की जानी चाहिए।



चारों विधान परिषद सीटों पर एनडीए की जीत के लिए जुटे कार्यकर्ता, विजयेन्द्र ने भरी हुंकार

करना समस्या का समाधान नहीं है; इसके बजाय भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और उम्मीदवाद का विश्वास बहाल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि पिछली भाषणा सरकारी के कार्यकाल में भी अनियमितताएं हुई थीं, तो उनको भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विजयेन्द्र भी सरकार के कार्यकाल में घोषणाएं पा जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। विजयेन्द्र ने बताया कि हनुली-धारावा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की तारीखों, साक्षात्कार और परिणामों में देरी के कारण सरकारी नौकरी की तारीफ कर रहे उम्मीदवारों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्रिस वे चुनावी वादे का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने राज्य में लगभग ढाई लाख रिक्त सरकारी पद भरने का आश्वासन दिया था। विजयेन्द्र ने सरकार से अब तक भरे गए पदों का विवरण सावजनिक करने, रिक्तियों की जल्द भरने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने की मांग की। विधान परिषद चुनाव से पहले विजयेन्द्र के इन बयानों से कर्नाटक में राजनीतिक आरोप-प्रचारों तेज होने के साथ ही चुनाब में एनडीए की रणनीति पर सफा-साथ कि सानों, युवाओं और सरकारी भर्ती से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों के दावों और आरोपों का आकलन संबंधित तथ्यों तथा आधिकारिक जानकारी के आधार पर किया जाना आवश्यक होगा।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
बैंगलुरु, 18 अक्टूबर 2026।
बेंगलुरु के विजयनगर क्षेत्र में स्थानीय
नागरिकों द्वारा आयोजित गणेश उत्सव
एवं नवरात्रि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि
महेंद्र मुणोत ने भगवान गणपति के दर्शन

कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर
उन्होंने अन्नदान कार्यक्रम में भी सेवा प्रदान
की। आयोजन समिति की ओर से मुणोत
को सम्मानित किया गया। धार्मिक अस्था
और सामाजिक सहभागिता के उद्देश्य से
आयोजित इस कार्यक्रम में भगवान
गणपति की पूजा-अर्चना के साथ सेवा

जलरतमोंद तक भोजन पहुंचाने की परंपरा
को प्रोत्साहित किया गया। भारतीय
संस्कृति में अन्नदान को सेवा और
परोपकार का महत्वपूर्ण माध्यम माना
जाता है। कार्यक्रम में महेंद्र मुणोत की
सहभागिता के दौरान आयोजकों ने उनका
सम्मान किया। गणेश उत्सव और नवरात्रि
जैसे पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ-साथ
समाज में आपसी सहयोग, सद्भाव और
सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देने का
अवसर भी प्रदान करते हैं। विजयनगर में
आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से
धार्मिक आयोजन और सामाजिक सेवा के
समन्वय की झलक देखने को मिली।
समाचार प्रेषक उपेन्द्र कुमार बैंगलुरु।

से संख्या बढ़ने से नागरिकों की समस्याओं का स्वतः समाधान नहीं होगा। इसके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यालयों का स्थापना, भवन निर्माण, सेवाओं को उपलब्धता और अन्य समसमयबद्ध शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाएं भी आवश्यक होंगी। नई प्रशासनिक इकाइयों के कामकाज की नियमित समीक्षा और स्थानीय लोगों से संवाद के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पुनर्गठन का वास्तविक लाभदायक दूरदराज के गांवों तक पहुंचे।

आठवां नई तहसीलों के गठन का फैसला प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अब इसकी सफलता इस बात से नागिकों की नई व्यवस्था आम नागरिकों के लिए कितनी सुलभ बनती है और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में कितना सुधार आता है।

आवासीय गतिविधियों के एक बड़े वेकें के रूप में तैयार करने की परिकल्पना है। रिपोर्टों में प्रस्तावित इमारत की तुलना दुर्बल स्थिति बुजुर्ग खलीफा से भी की गई है। बुजुर्ग खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। प्रस्तावित भारतीय इमारत यदि 700 मीटर ऊंची बनती है, तो वह इससे 128 मीटर छोटी होगी। हालांकि, परियोजना की औसत ऊंचाई और निर्माण संबंधी विवरणों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। निवेश और रोजगार की संभावनाएं इस परियोजना से करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की संभावना जताई गई है। यदि इतने बड़े स्तर पर निवेश होता है, तो इससे निर्माण, रियल एस्टेट, होटल, खुदरा कारोबार और अन्य संलग्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। रोजगार के अवसरों पर भी इसका

कौशल और तकनीकी अवधारणाओं की समझ उम्मीदवार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, नौकरी पाने में कठिनाई के पीछे केवल उम्मीदवार की तैयारी ही ज़िम्मेदार नहीं होती। उपलब्ध र्वित्तियां, कंपनियों की भर्ती नीति, अनुभव संबंधी अपेक्षाएं और आर्थिक परिस्थितियां भी रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती हैं। वास्तव में पोस्ट ने उठाए रोजगार से जुड़े सवाल युवक की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर शुरूआती स्तर की नौकरियों की उपलब्धता और तकनीकी डिग्री के बाद रोजगार की उम्मीदों जैसे मुद्दों को चर्चा में ला दिया है। पहली पैलरी देने की पेशकश उसके लिए नौकरी की अहमियत और रोजगार पाने की बेचैनी को दर्शाती है। यह घटना इस बात पर भी ध्यान दिलाती है कि तकनीकी शिक्षा और उद्योग की जरूरतों को भी बेहतर तालमेल किना महत्वपूर्ण है। गुवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुख कौशल और कस्मर मार्गदर्शन उपलब्ध करना नौकरी की तैयारी में सहायक हो सकता है।

किराए के मकानों में चल रही थीं दो ड्रमस लैब, एनसीबी ने 45 करोड़ रुपये का नशीला कारोबार पकड़ा

भारतार्थ खबर Bhaaraat.aarth.com

ग्रेटर नोएडा, 18 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अवैध सिंथेटिक ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए

संयुक्त राज्य के प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित है। इस मामले में एम्फेटामिन युक्त 379 किलोग्राम सामग्री और 10 किलोग्राम स्प्रूडोएफेड्रिन सहित विभिन्न रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 45 करोड़ रुपये बताई गई है। मामले में एक नाइजीरियाई नागरिक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिहायशी मकानों में चल रहा था अवैध कारोबार प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनसीबी ने ग्रेटर नोएडा के जहानाबाद कादलपुर गांव में कार्रवाई कर कार्रवाई के मकानों में संचालित दो अवैध सिंथेटिक ड्रग्स प्रयोगशालाओं का पता लगाया। जांच के दौरान इन स्थानों से नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और रासायन बरामद किए गए। कार्रवाई में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसीटोन और टोल्यून जैसे रासायन भी मिले। इनका उपयोग विभिन्न औद्योगिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में होता है, हालांकि किसी विशेष मामले में इनकी भूमिका का निर्धारण जांच के निष्कर्षों के आधार पर किया जा रहा है। 145 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त एनसीबी की कार्रवाई में बरामद सामग्री में 379 किलोग्राम एम्फेटामिन युक्त पदार्थ और 10 किलोग्राम स्प्रूडोएफेड्रिन शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार, जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये है। एम्फेटामिन एक शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ है, जिसका अवैध इस्तेमाल स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। वहीं, स्प्रूडोएफेड्रिन का उपयोग कुछ दवाओं के निर्माण में होता है और इसके अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए एनयामकीय नियंत्रण लागू हैं। दो आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी इस मामले में एनसीबी ने एक नाइजीरियाई नागरिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है जांच एजेंसी की कार्रवाई का उद्देश्य कथित अवैध प्रयोगशालाओं के संचालन और नशीले पदार्थों से जुड़े नेटवर्क का पता लगाना है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपियों की पहचान, कथित नेटवर्क के अन्य सदस्यों और नशीले पदार्थों की आपूर्ति के संभावित मार्गों का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है। इन पहलुओं पर जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर कार्रवाई अहम प्रक्रिया के आवश्यक परिणामों में कथित रूप से अवैध ड्रग्स प्रयोगशालाओं का संचालन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चुनौती है। ऐसे मामलों में केवल बरामदगी और गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि रसायनों की आपूर्ति, वित्तीय लेनदेन और नशीले पदार्थों के वितरण से जुड़े संभावित नेटवर्क की जांच भी महत्वपूर्ण होती है। ग्रेटर नोएडा में एनसीबी की इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में सामग्री की बरामदगी हुई है। अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा बाकी कि कथित प्रयोगशालाओं का संचालन कब से हो रहा था और इस गतिविधि से जुड़े अन्य लोगों की कोई भूमिका थी या नहीं।